ORIGINAL ARTICLE ISSN:- 2231-5063

Golden Research Thoughts

इक्कीसवी सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप

फरहाना हाशिम

असिस्टेन्ट प्रोफेसर , एस.बी.डी. महिला महाविद्यालय,धामपुर, जनपद बिजनौर ।

सारांश :-

भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के जिस पौधे को रोपित किया गया था, इक्कीसवी सदी के प्रारम्भिक वर्षो में यह फलीभूत होने लगा था। परिमाणतः वर्ष 2008 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल हो चुकी थी ।

प्रस्तावनाः—

वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि का दौर चला । इस अवधि में भारत में आर्थिक वृद्धि की औसत दर 9 प्रतिशत रही । वर्ष 2003 में भारत की इस रफतार को देखते हुए Goldman Sach ने भविष्यवाणी की, कि चालू कीमतों पर भारत का जी.डी.पी. फ्रांस तथा इटली को 2020 तक, जर्मनी एवं यू.के. व रशिया को 2025 तक तथा जापान को 2035 तक ओवरटेक कर लेगा और इस तरह भारत का नाम विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में लिया जाएगा ।

वर्ष 2008—09 में भारत में आर्थिक वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत हो गई परन्तु 2009—10 में यह दोबारा रिकवर होकर 7.4 प्रतिशत में तबदील हुई । वर्ष 2011—12 में आर्थिक वृद्धि दर यद्यपि 6.7 प्रतिशत रही, परन्तु क्रम शक्ति समता की (PPP) दृष्टि से भारत ने 2011 में ही विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया था । इससे पूर्व 2005 में भारत का इस मामले में विश्व में दसवां स्थान था । विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम की 30 अप्रैल 2014 को वाशिंगटन में जारी रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मामले में भारत का वर्ष 2011 में जहॉ तीसरा स्थान था वहीं प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. की दृश्टि से विश्व में भारत का 127वां स्थान था । विनिमय दर के आधार पर भारत वर्ष 2011 में वैश्विक जी.डी.पी. में केवल 2.7 प्रतिशत ही योगदान दे रहा था ।

वर्ष 2012 के प्रारम्भ में भारत एक ऐसे दौर में था जहां वैश्विक आर्थिक संगट तथा देश की आंतरिक नीतियों में आई कमजोरी ने आर्थिक वृद्धि दर को और अधिक गिराते हुए 4.5 प्रतिशत पर पहुॅचा दिया । इस समय अर्थव्यवस्था को अनेकानेक गम्भीर समस्याओं ने जकड़ लिया था, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर होता भारतीय रूपया, चालू खाते का घाटा, विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से तेजी से बाहर जाना एवं परिमाणात्मक बन्धनों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करने का दबाव इत्यादि ।

संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएशन एण्ड प्रोसपेक्टस रिपोट्र 2014 ने वर्ष 2013 में भारत की आर्थिक विकास दर 4.8 प्रतिशत रहने की घोशणा की है । इस रिपोर्ट में भारत के विकास का अनुमान पहले की अपेक्षा 1.3 प्रतिशत कम किया गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक विकास के सहायक महासचिव शमशाद अख्तर ने कहा है कि यह अनुमान कई खतरे और अनिश्चितता के सन्दर्भ में लगाया गया है ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी फरवरी 2014 के अग्रिम अनुमानों में 2013—14 में आर्थिक वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है ।

इक्कीसवीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की दशा एवं दिशा :—

उद्योग (Industry***) :—***

औद्योगिक क्षेत्र का जी.डी.पी. में जो हिस्सा 2004—05 की कीमतों पर 2010—11 में बढ़कर 28.2 प्रतिशत हो गया था वह 2011—12 में घटकर 27.5 प्रतिशत रहा । वर्ष 2012—13 हेतु यह 26.7 प्रतिशत अनुमानित है ।

वित्तीय वर्ष 2007—08 के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन दर (वृद्धि दर) 15.5 प्रतिशत रही थी, वर्ष 2009—10 में 5.3 प्रतिशत अनुमानित की गई । वर्ष 2010—11 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत तथा 2011—12 में 8.5 प्रतिशत अनुमानित है ।

यह आंकड़े वर्ष 2007—08 के बाद आई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर की कमी का प्रमाण है ।

सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हम 21वीं सदी में पुनः तीव्रतर विकास मार्ग पर चल पड़ें । इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम नया कम्पनी विधेयक—2012 है । कम्पनियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने एवं निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए बनाए गए इस नए कम्पनी विधेयक से जहॉ एक ओर निवेशक अधिक सुरक्षित हो जाएगा वहीं कम्पनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी करने का प्रयत्न करेगी ।

भारत में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या में तीव्र वृद्धि 2013—14 के दौरान हुई है जिससे यह संख्या अब चौदह लाख के निकट पहुॅच गई है । उद्योग चैबर फिक्की के अध्यक्ष सिद्धार्थ बिडला के अनुसार बीते कुछ महीनों में कारोबारी माहौल में सुधार हुआ है।[1]

विश्व की बड़ी कम्पनियों की फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में भारत की 54 कम्पनियों को जगह मिली है । फोर्ब्स अमरीकी वाणिज्यिक पत्रिका है जिसकी 2014 में जारी सूची में भारत की जिन 54 कम्पनियों को जगह मिली है उनमें शीर्ष पर 135वॉ स्थान रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है ।

कृषि (Agriculture***) :—***

नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में क्रमशः 2.5 प्रतिशत तथा 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई । यह वृद्धि दर आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई 4.72 प्रतिशत के मुकाबले बहुत कम है । बारवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास लक्ष्य 4 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत रहा ।

आर्थिक समीक्षा 2012—13 के अनुसार कुल रोजगार में कृषि तथा सम्बद्ध व्यवसाय का हिस्सा 58.2 प्रतिात था । निजी क्षेत्र का भारत में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय है । भारत विश्व में कृषि उत्पादों के 10 अग्रणी निर्यातकों में से भी एक है ।

इक्कीसवीं सदी में कृषि वृद्धि दर बढ़ाने के साथ साथ हमें इसके गुणात्मक पक्ष पर भी ध्यान देना होगा ताकि बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा में हम अपना स्थान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कायम रख सकें, यह आज आवश्यक हो चुका है ।

चालू वित्त वर्ष 2014—15 की पहली तिमाही में (अप्रैल—जून, 2014) कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत रही है जबकि एक साल पहले यह चार प्रतिषत थी । मानसून की बेरूखी से अगली तिमाही में इसमें कमी देखने को मिल सकती है ।[2] हालाकि नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स एण्ड पॉलिसी रिसर्च के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा, मुझे लगता है कि अगर पहली तिमाही में कृषि जी डी पी की रफतार पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 3.8 फीसदी रही तो यह प्रशंसनीय है । ऐसा इसलिए क्योंकि 2013—14 के उच्च आधार के बावजूद इसकी बढ़त की रफ्तार

में बहुत ज्यादा सुस्ती नहीं देखने को मिली ।[3]

सेवा (Services) :–

भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का भाग जो 1950–51 में 33.3 प्रतिशत था, वर्ष 2012–13 में बढ़कर 56.5 प्रतिशत हो गया है । निर्माण कार्य को शामिल करते हुए यह हिस्सा वर्ष 2012–13 में बढ़कर 64.8 प्रतिशत हो जाएगा ।

वर्ष 2004–05 से 2011–12 की अवधि में सेवा क्षेत्र का संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 10.0 प्रतिशत रही जो कि इसी अवधि में समग्र सकल घरेलू उत्पाद की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत से अधिक थी । साथ ही इस सदी में सेवा क्षेत्र की भूमिका का महतव वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवाओं में अप्रैल 2000 से नवम्बर 2012 के दौरान 36. 04 बिलियन डॉलर के निवेश में से सर्वाधिक सेवा क्षेत्र में होने से साबित होता है । इस तरह सेवा क्षेत्र सर्वाधिक एफ.डी. आई. आकर्शित करने में सफल रहा है । रोजगार नियोजन में भी सेवा क्षेत्र का योगदान 2009–10 में 25.30 प्रतिशत हो गया है । भारत के जी.डी.पी. में सेवा क्षेत्र का योगदान 6.8 प्रतिशत है । इस प्रकार आगामी समय में राष्ट्रीय आय, विदेशी निवेश, रोजगार, निर्यात प्रत्येक दृष्टि से सेवा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका रहेगी ।

अप्रैल–जून में सेवा क्षेत्र की बढत की रफतार 6.8 फीसदी रही जो कि पिछले साल की समान वअधि में 7.2 फीसदी थी । कारोबार, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्यूनिकेशंस जैसे क्षेत्रों में इसे पीछे खींचा ।[4]

पर्यटन (Toursim) :–

भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1966 में की गई थी । हर्ष का विषय है कि देश में विदेशी पर्यटक आगमन के साथ साथ स्वदेशी पर्यटन में भी वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है । सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नई राश्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 घोशित की थी जिसमें अन्य बातों के अलावा देश को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया । अप्रैल 2008 से 31 माच्र 2013 तक प्रारम्भ होने वाले होटलो को पॉच वर्ष का कर अवकाष भी सरकार द्वारा दिया गया । वर्तमान में आगमन वीजा यानि (Visa on Arrival) योजना भी लागू है । 2009–10 में भारत की GDP में पर्यटन का योगदान 6.8 प्रतिशत तथा कुल रोजगार सृजन में 10. 2 प्रतिशत था । पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति (अगस्त 2013) में बताया गया है कि पिछले दो वर्षो में भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटनों की संख्या में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी पर्यटको की भारत यात्रा से रू. 94,487 करोड़ की विदेशी मुद्रा 2012 के दौरान अंर्जित की गई।

विदेशी व्यापार एवं भुगतान सन्तुलन (Foreign Trade & Bafance of payment) :–

भारत का विदेशी व्यापार लगभग सभी देशों के साथ है । दिशानुसार भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमरीका से है । वित्तीय वर्ष 2011–12 में भी संयुक्त राज्य अमरीका भारत के निर्यातों का अकेला सबसे बड़ा खरीदार रहा ।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की एक ताजा रिर्पोट मे (वर्ल्ड ट्रेड रिर्पोट – 2011) बताया गया है कि वर्ष 2010में भारत का सेवाओ के निर्यात में विश्व मे 10 वॉ स्थान तथा वस्तुओ के निर्यात में 20 वॉ स्थान रहा । रिर्पोट के अनुसार वर्ष 2009 में सेवाओ एवं वस्तुओ के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में क्रमशः 12 वॉ तथा 22 वाँ था । सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा जो 2009 में 2.6 प्रतिशत या 2010 में बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो गया ।' सेवा निर्यात के क्षेत्र के मुख्य मद भारत में सूचना प्रौद्यागिकी (IT) तथा बिजनेस आउट सोर्सिग (BPO) का भी सबसे बड़ा बाजार अमरीका ही है, हालाकि यूरोप व एशिया के बाजारों में भी लगातार भारतीय IT एवं BPO क्षेत्रीय मांग बढ़ रही है ।

विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश 2001 से अब तक 2 प्रतिशत से कम ही रहा है । वर्ष 2006 में यह 1.00 प्रतिशत तथा तो 2012 में 1.60 प्रतिशत है ।

यदि वैश्विक आयातों की बात की जाए तो अमरीका की हिस्से दारी 12.6 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक है । भारत का 490 बिलियन डॉलर के आयात के साथ विश्व में 2.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी तथ दसवाँ स्थान था ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के चलते भारत के विदेशी व्यापार में भी शिथिलता आई है । वाणिज्य मंत्रपलय के उपर्युक्त अनन्तिम आँकडो के अनुसार वर्ष 2013–14 में निर्यात में 3.98 प्रतिशत वृद्धि तथा आयात में 8.11 प्रतिशत की कमी आई है ।

ताजा विदेश व्यापार नीति 2009–14 का उद्देश्य वर्ष 2014 तक देश के निर्यात को दोगुना करना है ।

भुगतान सन्तुलन :–भुगतान सन्तुलन खाते के दो भाग होते है – चालू खाता तथा पूँजी खाता । सर्वविदित है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए चालू खाते का संतुलन अत्याधिक महत्वपूर्ण है । वर्ष 2004–05 से चालू खाता घाटे की स्थिति में आ गया है । जैसा कि तालिका संख्या 2 से स्पष्ट हो रहा है चालू खाते का घाटा 2004–05 में G.D.P. का 0.4 प्रतिशत था तथा यह निरन्तर 2011–12 तक बढ़ता रहा

भुगतान सन्तुलन के प्रमुख सूचक 5
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)
तालिका संख्या 2

सूचक	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
निर्यात	13.6	13.4	15.2	13.4	14.8	N.A.
आयात	20.1	20.8	25.0	22.2	22.6	N.A.
व्यापार खाते का संतुलन	–6.5	–7.4	–9.7	–8.7	–7.4	–10.2
चालू खाते का संतुलन	–1.0	–1.3	–2.3	–2.8	–2.8	–4.2
विदेशी ऋण	17.5	18.0	20.3	18.2	17.5	19.7

Source – Economic Survey 2012-13

अप्रैल से सितम्बर 2013 के 6 महीनों में निर्यात वृद्धि तथा आयातों में गिरावट आनी शुरू हुई । व्यापार घाटे में सुधार तथा अदृश्य प्राप्तियों में लगातार वृद्धि से वर्ष 2012–13 की पहली तिमाही में चालू खाते का घाटा वर्ष G.D.P का 4.5 प्रतिशत तथा 2013–14 की पहली तिमाही में G.D.P. का 3.1 प्रतिशल हो गया है ।

भुगतान सन्तुलन में सुधार हेतु रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त, 1994 से रूपए चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया है ।

विदेशी ऋणभार :–

वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 2013 के अन्त में कुल 426.0 अरब डालर था, इसमें अल्पकालिक ऋण का भाग 21.8 प्रतिशत था, शेष दीर्घकालिक ऋण थे । वर्ष 2002 से अब तक विदेशी ऋण का भार देश पर लगातार बढ़ रहा है ।

मानव पूंजी निर्देशांक 2013 :–

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम द्वारा जारी मानव पूंजी रिपोर्ट 2013 में 122 देशों के बीच भारत 78वें स्थान पर है । स्वास्थ्य एवं तन्दरूस्ती सूचकांक में भारत 112वें, उचित वातावरण सृजन के मामले में 67वें, शिक्षा के मामले में 63वें तथा श्रम बल एवं रोजगार के मामले में 49वें स्थान पर है । लिंग भेद कम करने के मामले में हम 107वें स्थान पर है ।

वैश्विक भूख निर्देशांक 2013 :–

इण्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीटयूट (IFPRL) द्वारा जारी वैश्विक भूख इंडैक्स रिपोर्ट 2013 में बताया गया है कि भारत में वर्ष 2010–12 में अल्प पोषित जनसंख्या का अनुपात 17.5 प्रतिशत था ।

मुद्रास्फीति :–

मुद्रा सफीर्ति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है यद्यपि विकासषील अर्थव्यवस्था में हल्की सी मुद्रा स्फीर्ति टॉनिक का काम करती है परन्तु अनियंत्रित हो जाने पर यह हानिप्रद है ।

मुद्रास्फीति की दर (प्रतिशत में) [8]

मार्च 2013	फरवरी 2014	मार्च 2014
5.65	4.68	5.70

महंगाई के मोर्चे पर सरकार के समक्ष चुनौतियॉ अब भी बरकरार हैं । सबसे बड़ी चुनौती खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना है । खाद्य वस्तुओं की मुद्रा स्फीर्ति दर 9.42 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है ।6 खाद्य स्फीर्ति को नियंत्रित करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसका सर्वाधिक नुकसान गरीब आदमी को होता है । दूसरी चुनौती यह है कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले गांवों में महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है । केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल अगस्त में फलों की कीमतों में 24.27 प्रतिशत, सब्जियों में 15.15 प्रतिशत और दुग्ध उत्पादों के मूल्य में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।7

वैश्विक दासता निर्देशांक 2013 में भारत शीर्ष स्थान पर :–

आस्ट्रेलिया स्थित वाक फ्री फाउण्डेशन द्वारा तैयार की गई सूची में वैश्विक दासता निर्देशांक 2013 के आधार पर विश्व में दासता का जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्तियों की संख्या भारत में सर्वाधिक है । भारत में 14 (चौदह) मिलियन लोग आधुनिक दासता का षिकार है ।

निष्कर्ष :–

मुश्किल दौर से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था का कठिन वक्त अब खत्म हो रहा है । अर्थव्यवस्था सही नीतियॉ अपनाने से आने वाले समय में और मजबूत होकर उभरेगी । वास्तविकता तो यह है कि अब स्थितियां बदल रही है और वर्तमान पहले से बहुत बेहतर हो चुका है । विदेशी निवेशक भारत की ओर कदम बढ़ाने लगे हैं । अर्नेस्ट एवं यंग की हालिया पूंजी विश्वस्त मापन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक निवेशकों के लिए भारत सबसे ज्यादा आकर्षक निवेश स्थल है । भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सम्बन्धी नीतियों में उदारता बरते जाने के कारण निवेशकों ने अमरीका तथा चीन की तुलना से भारत को प्रथमिकता दी है । ई एण्ड वाई द्वारा किए गए सर्वेक्षण में वर्ष 2013 में सर्वाधिक आकर्षक निवेश स्थलों की सूची में भारत प्रथम स्थान पर, ब्राजील एवं चीन क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है । भारत

में ऑटो मोबाइल्स प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञानों तथा उपभोक्ता उद्योगों में निवेश की बेहतर सम्भावनाएं है ।

जीडीपी का क्षेत्रवार प्रदर्शन

क्षेत्र	2013–14 पहली तिमाही	2014–15 पहली तिमाही
कृषि	4 फीसदी	3.8 फीसदी
उद्योग	–0.4 फीसदी	4.2 फीसदी
सेवा	7.2 फीसदी	6.8 फीसदी
कुल	4.7 फीसदी	5.7 फीसदी

स्त्रोत बिजनेस स्टैंडर्ड शनिवार 30 अगस्त, 2014

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक विकास की दर 5.7 फीसदी पर पहुॅच गई है । बीते ढाई साल में यह तिमाही आंकडा सर्वाधिक है ।9 एसोचैन के अध्यक्ष राणा कपूर ने कहा है कि जी.डी.पी. के वृद्धि दर अभी और बढेगी । वित्तीय वर्ष 2014–15 में यह छः फीसदी के स्तर को पार कर सकती है ।10 चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की आर्थिक विकास दर की तरह, चालू खाते का घाटे का आंकडा भी सरकार के लिए उत्साहवर्धक रहा है । अप्रैल से जून की तिमाही में यह घाटा जी.डी.पी. का 1.7 फीसदी रहा है ।11 इसका मुख्य कारण सोने के आयात में कमी तथा विदेशी व्यापार घाटे का कम होना है । आने वाली तिमाहियों में मानसून की अटपटी चाल से परिदृश्य थोड़ा परिवर्तित भी हो सकता है, क्योंकि कृषि उत्पादन में कमी नकारात्मक प्रभाव डालेगी । पहली तिमाही में खनन क्षेत्र पर भी दबाव देखा गया है और उच्चतम न्यायालय के आदेश से इस क्षेत्र की ओर भी झटका लग सकता है ।

यस बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री षुभदा राव ने कहा, ''अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उम्मीद के अनुरूप है । हालांकि कृषि और सेवा क्षेत्र के व्यापार और होटल खंड में उम्मीद के अनुरूप सुधार नहीं देखा गया ।12

आवश्यकता इस बात की है कि सुधारों की गति को और तेज किया जाए तथा गैर जरूरी खर्चो पर रोक लगाई जाये । अधिकांश अर्थशास्त्री भारत को आज सुपरपावर के रूप में उभरता हुआ देख रहे हैं । इस बात में कोई संदेह नहीं कि इक्कीसवी सदी में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । स्टॉक मार्केट का नई ऊँचाईयों को छूना और विशेषकर चालू खाते के घाटे में सुधार जैसे सकारात्मक लक्षण अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार के संकेतक हैं ।

मजबूत एवं स्थाई सरकार, सुधारात्मक कदम तथा नीतियों ने अर्थव्यवस्था में प्राणवायु का कार्य किया है । देष में और विदेशो में अब भारत को लेकर सकारात्मक सोच बनी है ।

संदर्भ सूची :–

1.आर्थिक विकास की रफ्तार से उद्योग जगत चहका, दैनिक जागरण, मेरठ संस्करण, 30 अगस्त 2014
2.अर्थव्यवस्था के आए अच्छे दिन, दैनिक जागरण, मेरठ 30 अगस्त 2014, पृष्ठ सं0 15
3.उद्योग में सुधार की तेज रफ्तार, ईशान बख्शी, बिजनेस स्टैडर्ड, नई दिल्ली 30 अगस्त, 2014, पृष्ठ सं. 3
4.उद्योग में सुधार की तेज रफ्तार, ईशान बख्शी, बिजनेस स्टैडर्ड, नई दिल्ली 30 अगस्त 2014, पृष्ठ सं. 3
5.आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13
6.महंगाई घटी, मैन्यूफैक्चरिंग की चुनौती अभी बरकरार, दैनिक जागरण, मेरठ 13 सितम्बर 2014, पृष्ठ सं. 13
7.महंगाई घटी, मैन्यूफैक्चरिंग की चुनौती अभी बरकरार, दैनिक जागरण, मेरठ 13 सितम्बर 2014, पृष्ठ सं. 13
8.प्रतियोगिता दर्पण जून 2014, पृष्ठ सं0 26
9.अर्थव्यवस्था के आए अच्छे दिन, दैनिक जागरकण, 30 अगस्त 2014, पृष्ठ सं. 15
10.अर्थव्यवस्था के आए अच्छे दिन, दैनिक जागरकण, 30 अगस्त 2014,पृष्ठ सं. 15
11.बुनियादी उद्योगों का कमजोर प्रदर्शन, चालू खाते का घाटा हुआ कम, दैनिक जागरण, मेरठ 2 सितम्बर, 2014, पृष्ठ संख्या 13
12.उद्योगों ने दौड़ाया विकास का पहिया, बिजनेस स्टैंडर्ड शनिवार 30 अगस्त, 2014, पृष्ठ संख्या 1